राजनीति का व्यावसायोकरण : बजरंग मुनि

भारतीय व्यवस्था में समाज की भूमिका सर्वोच्च होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति या समूह के कार्य समाज केन्द्रित होते हैं। यदि कोई विद्वान होता है तो वह विद्वता के माध्यम से समाज को सशक्त करता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इन ब्राह्मणों का ही अतिवादी स्वरूप धर्म गुरू अथवा सन्यासी के रूप में दिखाई देता है। जो समाज को न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें राजनेता कहा जाता है, ये प्राचीन समय में क्षत्रिय कहे जाते थे। इनका अतिवादी स्वरूप राजा के रूप में प्रकट होता था। जो समाज को आर्थिक दृष्टि से सहायता करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, जिन्हें आज कल व्यापारी कहते हैं। जो लोग इन तीन प्रकार की योग्यताओं से अक्षम होते थे वे स्वयं या तीनों वर्गों की सहायता करके समाज को सशक्त करते थे। इन्हें वर्तमान में श्रमिक तथा प्राचीन समय में शूद्र कहा जाता था। वैश्य के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ग यदि व्यवसाय करता अथवा सीमा से अधिक धन संग्रह करता था तो उसे अपना वर्ण बदलकर वैश्य या व्यापारी मान लिया जाता था। इस तरह चारों वर्ग अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपनी अपनी क्षमतानुसार समाज सशक्तिकरण का काम करते थे। जब से अंग्रेज भारत में आये तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार समाज को तोडा और समाज सशक्तिकरण में लगे चारों वर्णों का व्यवसायीकरण कर दिया जो स्वतंत्रता के बाद भी न सिर्फ जारी है बल्कि बहुत तेजी से फल फूल रहा है।

वर्तमान समय में सब प्रकार के क्षेत्र अपने अपने सामाजिक कार्य को व्यवसाय मानकर करने लगे हैं। धर्म क्षेत्र में लगे चाहे निर्मल बाबा हो या आशाराम बापू, चाहे बाबा रामदेव हो अथवा रवि शंकर महाराज, सभी अधिकतम धन संग्रह करने और धन के माध्यम से स्वयं को स्थापित करने में लगे हैं। इनके सभी कार्य चाहे वे कोई भी कार्य क्यों न हो शुद्ध रूप से व्यवसाय है या शुद्ध रूप से व्यापार है। यदि हम खिलाड़ियो की चर्चा करें तो खेल के नाम पर जो भी लोग आगे आ रहे हैं वे अपने कार्य को शुद्ध व्यापार का स्वरूप दे रहे है चाहे वे सचिन तेन्दुलकर हो या कोई और । न खेलों में कहीं समाज सेवा का भाव छुपा है और न देश सेवा का। सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का ही भाव छिपा है, जिसे कभी समाज सेवा का नाम दे दिया जाता है तो कभी देश सेवा का। सामाजिक संगठन के नाम पर एनजीआ या अन्य संगठन भी इसी व्यावसायिक दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे है। साहित्य समाचार पत्र अथवा मीडिया के अन्य साधन भी अप्रत्यक्षतः व्यवसायी हो चुके हैं। धर्म गुरूओं, खिलाड़िओं अथवा एनजीआ वालों ने तो व्यवसाय और समाज सेवा के बीच अब भो एक हल्का पर्दा बनाये रखा है। परन्तु मोडिया वालों ने तो वह पर्दा भी हटा दिया है। फिर भी यह लेख लिखने का हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति के व्यावसायोकरण से जुड़ा है। अतः हम राजनीति पर विशेष चर्चा करेंगे।

वैसे तो स्वतत्रता के बाद ही राजनीति के व्यवसायोकरण की शुरूआत हो गई थी किन्तु यह आशिंक रूप से थी, ढ़के छुपे थी। अब तो राजनीति बिल्कुल नग्न स्वरूप में व्यवसाय के रूप में खड़ी हो गयी है। राजनीति में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पंच, सरपंच हो अथवा विधायक। चाहे वह विधायक मंत्री हो अथवा सांसद और प्रधानमंत्री। एक दो को छोड़कर लगभग सभी राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं। कुछ लोग अब भी अपने मुख्य व्यवसाय के साथ साथ आंशिक रूप से राजनीति का व्यवसाय करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सारे व्यावसायिक काम छोड़कर पूरा समय इसी व्यवसाय म लगाते हैं। जिस तरह व्यवसाय करने वालों को व्यावसायिक ठेके प्राप्त होते हैं तथा जिसे ठेका कहीं नहीं मिलता वह निराश हो जाता है उसी तरह राजनीति में भी सत्ता के पद व्यावसायिक ठेके के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मीडिया में तो एक परदे का आभास भी होता है परन्तु राजनीति ने तो वह आभास भी कराना बंद कर दिया है। वैसे तो अब राजनीति से न समाज सेवा का कोई सम्बन्ध रहा है न दलीय सिद्धांतों का, किन्तु वर्तमान समय में तो जिस तरह दलीय निष्ठाएं मिनटों में बदली जा रही है और वह भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और वह भो बिल्कुल सड़क पर नंगे होकर वह वास्तव में चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता टिकट न मिलने की घोषणा होते हीं दूसरी दुकानों पर चले जाते हैं। उससे तो दर्शकों को भी शर्म आने लग जाती है। ऐसी नग्नता तो सिनेमा के ऐक्टर भी एडल्ट फिल्मा में भी नहीं दिखाते। वहॉ भी कलाकार कामुकता को उभारते समय कुछ सीमा में रहते हैं। परन्तु राजनीति में तो अब वह सीमा भी नहीं रही। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलते ही उसके एक नेता ने मध्य प्रदेश में जहर खाकर अपनी जान दे दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की स्थापित नेत्री करूणा शुक्ला ने टिकट नहीं मिलते ही कांग्रेस पार्टी के साथ ऑख मिलाना शुरू कर दिया। देश भर में हर पार्टी के प्रमुख लोगों ने या तो टिकट बेचे या टिकट न प्राप्त होने वालों ने उन पर टिकट बेचने के आरोप लगाये। मायावती सरीखें दलो पर तो ऐसे आरोप लगते ही हैं किन्तु अब तो कांग्रेस और भाजपा भी ऐसे आरोपों से दूर नहीं है। राज्य सभा की सीटें पूंजीपतिओं को बेचने की तो लगभग परपरा ही बन गई है। चुनावों में जीतने के लिए करोड़ों रूपया खर्च करना और जोतने के बाद अरबों रूपया कमाने की व्यवस्था करना हीं वर्तमान राजनीति का एक मात्र कार्य रह गया है। मनमोहन सिंह सरीखे जो लोग ऐसे व्यवसाय में फिट नहीं रहे हैं उनकी दुर्गति भी दिख रही है। संघ परिवार ने बहुत समय तक चरित्र की राजनीति की उसे भी हार थक कर अब नरेन्द्र मोदी सरीखे अति चालाक राजनेता की शरण में जाना पड़ा है। लगता है कि अब राजनीति भी पूरी तरह खिलाड़ियों, कलाकारों पाखंडी धर्म गुरूओं से भिन्न कोई अलग आदर्श की सम्भावना में नहीं रही है।

प्रश्न उठता है कि जब विद्वान लेखक, कलाकार, राजनेता धर्म गुरू सरीखे समाज सशक्तिकरण के स्तम्भ ही समाज कमजोरीकरण में लग जायेंगे तो समाज का क्या होगा यह चिंता का विषय है। ये लोग न सिर्फ समाज को कमजोर कर रहे हैं बल्कि राजनेता तथा धर्म गुरू तो समाज को धाखा भी दे रहे हैं। फिर भी यदि हम साहित्यकारों, धर्मगुरूओ, खिलाड़ियों, कलाकारों, मीडिया कर्मियों की राजनेताओं से तुलना करें तो राजनेताओं को छोड़ कर अन्य सब लोग भले ही समाज को धोखा दे रहे हों किन्तु वे समाज को किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहे हैं। आम लोग भले ही इनके प्रभाव में आकर इनसे चिपक जावे या ठगे जायें लेकिन इनका कोई कार्य समाज पर बंधनकारी नहीं है। जबकि राजनेताओं के आदेश समाज पर बंधनकारी होते हैं। वे जब चाहें जितना चाहें टैक्स लगा सकते हैं। चिंता का विषय है कि समाज सशक्तिकरण का कार्य कहॉ से शुरू हागा? कैसे शुरू होगा? कौन शुरू करेगा? अभी तो राजनेताओं का चरित्र देख देख कर गहरा अॅधेरा ही दिखता है। शायद दीपावली के अवसर पर कोई ऐसा दीप जले जो उड़ीसा में आये भयानक तूफान से भी टकराकर अपने अस्तित्व को बचा सके।

सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन ही है समाधान!

रमेश चौबे, सचिव लोक स्वराज्य मंच

भारत में आजादी के बाद जितनी भी सरकारें अब तक बनी है, वे सभी अब तक लोकतंत्र को स्थापित करने में फेल ही रही है। एक तरफ आम आदमी को अवसर, न्याय और सुरक्षा देने में ये अब तक नाकाम ही रही है और दूसरी तरफ वह देश के पाकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का माध्यम बनती जा रही है। आज आजादी के नाम पर जो दिखता है उसमें आज भी हमें गहरी गुलामी दिखती है। सत्ता में बैठे लोगों ने षड़यंत्र पूर्ण तरीके से आम आदमी को गुलाम रखने के उद्देश्य से लोकतंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र के बदले लोक नियुक्त तंत्र की परिधि तक ही सीमित कर दिया है। आज सरकार का मतलब शासन हो गया है और शासन मनुष्य को सहज स्वीकार्य नहीं है, व्यवस्था स्वीकार्य है। शासन में जो काम हो रहा है वह लोगों की जरूरतों को समझे बगैर हो रहा है। आज सरकार कुछ अच्छे लोगों की भी बन जाएगी तो भी सफल नहीं होगी कारण कि 67 वर्षों में अब तक कई प्रयोग देश में हो चुके है। भारत की जनता अब तक कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों को आजमाकर देख चुकी है। इन सबके पीछे विफलता का मुख्य कारण ये भी है क्योंकि अब तक इसमें व्यक्ति, परिवार, गांव और समाज की आवश्यकता कोई दूसरा पहचानता है, योजना दूसरा ही बनाता है और उसे दूसरा ही कियान्वित करता है। जबकि यह एक अव्यावहारिक एवं अप्राकृतिक बात है।

भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जब लोगों का लगा है कि शासन, राजतंत्र उन्हें कमजार कर रहे हैं। इतिहास में कई तरह के प्रयोग हुए हैं। आज हमें उन्ह समझने की आवश्यकता दिखती है। आज जो परिवर्तन वाले लोग हमें दिख रहे हैं, वो चाहे वाम धाराओं के थे, या फिर समाजवादी धाराओं के थे, या और धारा के थे, वे आज थक गए, उनका जोश ढीला दिखता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आंदोलन कर रहे थे वे आज कहीं न कहीं सता सुख में भागीदार बन गए हैं। अब तक जो व्यवस्था परिवर्तन अभियान म लगने वाले हैं मेरी दृष्टि में वे सता परिवर्तन से आगे जाते नहीं दिखते। अब तक का अनुभव रहा है कि उनकी परिणति एक दल की जगह दूसरे दल की सरकार बनाने बनवाने मे ही है। आज की जो समस्याए है जैसे जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा, चरित्र पतन आदि ये लक्षण है समस्याए गहरी है। गहरी समस्यायो के जो रूप दिखते है वो दो सभ्यताओ के कमजोर पक्ष के रूप मे भारत मे एक साथ हावी हैं पूरब और पश्चिम की सभ्यताओ के जो नकारात्मक पक्ष थे वे आज अपने देश मे हावी है। और दुनियां मे भी हावी है । पश्चिमी सभ्यता मे भी कुछ अच्छी चीजे थी वे दबी हुई है और इस समय वहां भी कब्जेवाजी का ही प्रयास है। अमेरिका और युरोप मे जो सुविधाए लोगो को देने की कोशिश की गई वह अपने आप मे असफल सिद्ध हो चुकी है। दुनियां को गुलाम या उपनिवेश बना कर या समानता के आधार पर फंसा कर आधुनिकता चल रही है। उधर जो भारतीय पक्ष है वह राष्ट्रीयता और सामाजिकता के भावनात्मक पक्षो पर खरा नही उतर पा रहा हैं। धर्म और अध्यात्म भी इसमे शामिल है। आदमी और आदमी के रिश्ते का यहां स्वीकार नही किया जा रहा। जैसे हमने छुआछूत को कानून के रूप मे तो दूर कर लिया लेकिन आदमी आदमी के बीच अभी दूरियां है उसे अब तक खत्म नही किया जा सकता। यह कलंक मुझे भारतीय पक्ष मे ज्यादा ही दिखता है। मुझे लगता है कि सामाजिक समता समरसता के मामले मे हम कही उचे रहे होगें। लेकिन इस समय तो हम कही असफल हो चुके है। हम इसे गहराई मे कहें तो अपनी संस्कृति मे समाज एक बडे वर्ग को हिस्सेदार नही बना सका । किसान कारीगर मजदूर मुझे संस्कृति मे बहिष्कृत लोग नजर आते है। कुछ अच्छी बाते भी रही लेकिन सामाजिक ढंग से विश्लेषण करते है तो पूरब और पश्चिम दोनो ही सभ्यताओ के नकारात्मक पक्ष यानि उनकी कमजोरीयां इस समय देश दुनियां मे हावी है। दोनो ही के अच्छे पक्ष भी थे लेकिन उन्हे नजर अंदाज कर दिया।

हम देख रहे है आज जिस तरह दुनियां मे दूरियां घट रही है उस रूप मे पश्चिम वाले अपनी सभ्यता के प्रति अहंकार का भाव रखे हुए है। ऐसी परिस्थिति मे हम अपने को श्रेष्ठ बताये । इस संघर्ष की जगह एक ऐसी सभ्यता की जरूरत दिखती है जो मानवीय हो हर धर्म मजहव को स्वीकार हो। इस पर यदि हम काम नही कर पायेंगे तो छोटे छोटे राहत कार्यक्रम तक ही हम सीमित रह जायेगे। एक बात स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था मे श्रम का अपमान हुआ सम्मान नही हुआ । जितनी भी तकनीकी हमारे यहां विकसित हुई उसमे हाथो या पशुओ से चलने वाले यंत्रो पर कोई मौलिक काम अच्छे दिमांग से या किसी अच्छे संस्थान द्वारा नही हुआ। इन लोगो ने जो काम किया वो सारा उस दिशा मे किया जो पेट्रोल पर आधारित है। गैस बिजली कोयले आदि पर आधारित है प्राकृतिक व्यवस्था पर ध्यान नही गया और समाज का जो बडा तबका जो उस तकनीक से अपनी आजीविका आज चलाता था आज वह मजदूर बनकर शहर मे जाने को मजबूर है।

आज जब हम यह कहते है कि इस सरकार को पश्चिम की सरकार चला रही है। किसके हाथ मे ताकत है ? कहां से क्रान्ति आ रही है। कौन प्रेरणा दे रहा है? जिस व्यवस्था का संकट है समाधान वही से आयेगा। मै इस बात से सहमत नही हूँ कि इस संविधान के तहत समाधान तलाशे जाये । संविधान मे जब सही व्यक्ति की पहचान नही तो संविधान को कैसे ढोऐगे। देश के सम्मान के लिये हम उसका विरोध नही करेंगे। परन्तु देश दोषपूर्ण संविधान को दरूस्त तो अवश्य करेंगे एंव देश हित मे हमे करना भी होगा। एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ हम उस संविधान को स्वीकार तो करते है लेकिन देश काल व परिस्थिति अनुसार इसकी पूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय संविधान की पूर्ण समीक्षा होनी ही चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश मे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अभी हमारा ध्यान सत्ता परिवर्तन को ओर ही ज्यादा है। किसी का 2014 के चुनाव पर ध्यान है। तो किसी का उससे अगले चुनाव पर ध्यान है। देश की वर्तमान परिस्थितिया को देखते हुए व्यवस्था परिर्वतन के सम्बंध मे मेरा स्पष्ट मानना है कि वर्तमान काल की मांग है कि राजनीति पर समाज हावी हो। मेरा यह भी मानाना है कि इसके लिये भारत एक राजनीतिक दर्शन हेतु तैयार है। लोक स्वराज मंच इस दिशा मे लगा हुआ है। इसका स्थापित करने की तैयारी मे हम जुटे हुए है।

कार्यलयीन प्रश्नो के उत्तर

1 प्रश्न संग्रह कर्ता

1 श्री रमेश चौबे, पटना बिहार

2 श्री राजीव सिंह, वाराणसी उ.प्र.

3 श्री पुष्पेन्द्र रावत , दुर्ग छत्तीसगढ

प्रश्न1 ज्ञान तत्व अंक 277 के संदर्भ मे प्रश्न

क्या देश मे समान सम्पत्ति कानून की आवश्यकता नही है? फिर संयुक्त हिन्दू प्रोपर्टी कानून मुस्लिमो मे अलग राज्यो मे अलग अलग आदिवासी समाज मे अलग अलग । क्या समरूप सम्पत्ति कानून की संवैधानिक अनिवार्यता भारत मे भी आवश्यक नही होनी चाहिये? आपके अनुसार सम्पत्ति उत्तराधिकार या हस्तातरण कानून क्या होना चाहिये? ''पावर आफ प्रोपर्टी'' का संवैधानिक प्रारूप क्या होना चाहिये ताकि बढते हुए सम्पत्ति विवाद को हमेशा के लिये खत्म किया जा सके और संवैधानिक रूप से भी बाध्यकारी बनाया जा सके?

उत्तरः— भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार अर्जित सम्पति रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि संम्पति रखना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राज्य न उसके संम्पति संग्रह मे कोई बाधा पैदा कर सकता है न उसकी कोई सीमा बना सकता है। हर निकम्मा चाहता है कि अधिकतम संम्पति की सीमा बनाकर वह धन निकम्मे गरीबों में बॉट दिया जाए। यह नारा बहुत आर्कषक भी होता है तथा न्याय संगत भी है, इसलिये हर राजनेता विपक्ष मे होने पर इस नारे का उपयोग करता है और सत्ता मे होने पर इसके लिये कुछ नही कर पाता क्योकि न्याय संगत तथा जन आकर्षक होते हुए भी ऐसा करना व्यवस्था के जिए बहुत घातक होता है। ऐसे प्रयोग दुनिया मे जहॉ जहॉ भी हुए वहॉ उसके घातक परिणाम सर्वविदित ही है। फिर भी राज्य का कर्तव्य है, दायित्व नही, कि न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी असीमित ना हा जावे ऐसी अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था के पारूप को लागू करे। वर्तमान समय मे यह दूरी असीमित दिख रही है। एक ओर बीस करोड व्यक्ति अठाइस रूपये से भी कम पर जीवन जीने के लिये मजब्र हैं तो दूसरी ओर कुछ मुठठी भर लोग करोडों रूपया प्रतिदिन तक कमा रहें हैं। श्रम, बुद्धि और धन की कमाने की क्षमता में श्रम लगातार पिछड रहा है। श्रम खरीदने वाला ऐसे तर्क गढ रहा है जिससे श्रम बेचने वाले की मजबूरी लगातार बनी रहे। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के साथ मिलकर निम्न वर्ग को मजब्र बनाये रखने की योजनाऍ बनाते रहता है। यह भले ही कोई अपराध न हा किन्तु अनैतिक भी है और अन्यायपूर्ण भी। अतः राज्य को इस पर विचार करना चाहिए।

आम तौर पर संम्पति विवाद परिवारों से ही शुरू होते है। ये संम्पति विवाद डॉ. अम्बडकर की देन है। उन्हाने ही प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक अधिकार न देकर उन्हें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, हरिजन, महिला, पुरूष, युवा, वृद्ध आदि अनगिनत टुकडों मे बॉट दिया। वे तो आग लगाकर चले गए, किन्तु उस आग के परिणाम स्वरूप आज भी एक दो प्रतिशत राजनेता उस आग मे अपनी रोंटियॉ पका रहें है, और शेष अधिसंख्य आबादी उसमें झुलस रही है। यह डॉ. अम्बेडकर की ही देन है कि उन्होंनें परिवार मे रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत संम्पति रखने की छूट दे दी। सारे पारिवारिक मुकदमों की जड यही छूट है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिवार मे रहने की छूट है। यदि उसे अपना परिवार पंसंद नही है तो वह पृथक परिवार भी बना सकता है, किन्तु प्रत्येक परिवार मे उसे पृथक संम्पति की छूट नही होगी, बल्कि पूरे परिवार की संम्पति सामूहिक होगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य का समान हिस्सा होगा। महिला को गुजारा भत्ता तो पैतृक परिवार की संम्पति और स्वयं अर्जित संम्पति जैसे अलग अलग कानून बनाकर परिवार तोडक, समाज तोडक, कानूनों को समाप्त करने की आवश्यकता है न कि परिवार मे ऐसे जटिल कानून बनाये जाने की। मेरे विचार से अब ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिसमें परिवार को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जिसके प्रत्येक सदस्य को परिवार की संम्पति में समान हिस्सेदारी हो।

प्रश्न—2 आपके कथनानुसार परिवार मे सम्मिलित होने के बाद महिला तथा पुरूष का अलग से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नही होता । तब तक नही होता जब तक वह उस परिवार का सदस्य है। आप महिला और पुरूष को एक इकाई के रूप मे गणना करते है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वतंत्र अस्तित्व व अधिकार होते है। वैचारिक भिन्नता प्रकृति प्रदत्त मानवीय स्वभाव ह। ऐसे मे जब दो व्यक्ति महिला एव पुरूष वैचारिक रूप से व भौतिक रूप से अपने अपने अस्तित्व और स्वतंत्र पहचान के लिये संवैधानिक दृष्टि और प्राकृतिक रूप से दो ध्रुवीय है। ऐसी हालत मे इसे एक इकाई समझना कहां तक न्यायोचित है। पुरूष और महिला को एक इकाई के रूप मे गणना कैसे तर्क संगत हो सकता है।

उत्तर समान नागरिक संहिता का यह अर्थ नही है कि व्यक्ति के अपने स्वंतत्र अधिकार नही होंगें। व्यक्ति और नागरिक एक न होकर बिल्कुल अलग होतें हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार अलग होंते हैं तथा नागरिक अधिकार अलग। किसी परिवार का सदस्य होने के बाद भी

उसके मौलिक अधिकार व्यक्तिगत होंगें जिन्हें न राष्ट्र छीन सकता है न समाज न परिवार। किन्तु परिवार एक संगठन है तथा संगठन में शामिल हाना न होना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है किन्तु संगठन मे शामिल होने के बाद मूल अधिकारों को छोडकर अन्य मामलों मे उसके अधिकार सामूहिक हो जातें हैं अर्थात वह व्यक्ति भी होता है और नागरिक भी। व्यक्ति के रूप मे उसके अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं आर नागरिक के रूप संविधान प्रदत्त। चाहे कोई महिला हो या पुरूष, परिवार मे रहते हुए उसका पृथक अस्तित्व कैसे तो संभव है और क्यों होना चाहिए? यदि कोई महिला या पुरूष परिवार की सहमति के बिना अपना पृथक अस्तित्व बनाने का प्रयास करतें हैं तो यह परिवार के साथ चोरी है। या तो ऐसे सदस्य को ऐसी चोरी करने के पूर्व ही परिवार छोड देना चाहिए अन्यथा परिवार ऐसे चोर सदस्य को कभी भी परिवार से अलग कर सकता है। स्वतंत्र अधिकार का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नही है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की अपनी अलग सीमा रेखा है तो पारिवारिक अधिकारों की अलग। न व्यक्ति अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर किसी अन्य की सीमा रेखा मे दखल दे सकता है न ही परिवार व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमा रेखा मे घुस सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं को मूल अधिकारों की ठीक से समझ नही थी तथा उन्होने पश्चिमी लोकतंत्र की नकल करके ऐसी ऐसी भयानक भूलें कर दीं । अब हमें चाहिए कि हम नये सिरे से चर्चा करके ऐसी भूलों को सुधारने का प्रयास करें।

प्रश्न– 3 आप वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों पर पैनी नजर रखते हुए उसका मूल्यांकन एंव समीक्षा करते है। देश मे दो ध्रुवीय राजनीति चल रही है। बल्कि दो व्यक्तित्व आधारित राजनीति का ध्रुवोकरण कर दिया गया है। आसन्न लोक सभा चुनाव 2014 मे नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लडाई होने वाली दिख रही है। आप व्यवस्था परिवर्तन व लोक तंत्रीय मूल्य की वास्तविक स्थापित लोक स्वराज्य के पैरोकार व ऐसे अभियानो के प्रबल मुखर बहुचर्चित समर्थक रहे है। कृपया सम्पूर्णता के परिपेक्ष्य मे कोई निर्णायक निष्कर्ष के जरिये अपनी स्पष्ट राय दे कि वर्तमान परिस्थिति मे देश को नरेन्द्र मोदी या राहुल गांधी मे से किसकी आवश्यकता है और क्या एक स्थापित चिन्तक विश्लेषक की स्पष्ट राय देशहित मे आवश्यक है?

उत्तर –ऐसा कहना उचित नही होगा कि दो हजार चौदह के चुनाव नरेन्द्र मोदी तथा राहुल गांधी के बीच होने जा रहे है । नरेन्द्र मोदी इसे लगातार द्विपक्षोय बताने की और बनाने की कोशिश कर रहे है और अभी ऐसा दिखने भी लगा है जो न तो राजनैतिक रूप से आवश्यक है न कानूनी रूप से । कानूनी रूप से स्पष्ट है कि संसद मे बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। दो हजार चार मे सीधा मुकाबला अटल जी और सोनियां जी के बीच था। फिर बीच मे एकाएक मनमोहन सिंह कहां से आ गये। आप राजनीति क गिरते चरित्र को अच्छी तरह जानते है। यदि प्रशासनिक क्षमता तथा कार्यकुशलता को मापदण्ड माना गया तो नरेन्द्र मोदी सबसे आगे दिख रहे है किन्तु यदि लोकतंत्र चरित्र और धर्मनिरपेक्षता मापदण्ड बना तो नरेन्द्र मोदी सबसे पिछले पायदान पर खडे है। चुनाव अनेक जातीय धामिक स्थानीय क्षेत्रोय तथा उन सबके उपर भी चुनाव के बाद होने वालो सौदेबाजी पर निर्भर करते है। आप प्रधानमंत्री की संभावना से राहुल गांधी को खारिज कर सकते है किन्तु नीतिश कुमार मायावती मुलायम सिंह जैसे घाध लोगो की संभावनाओ को खारिज नही कर सकते। जहां तक अकन्द्रियकरण विकेन्द्रीकरण, लोकस्वराज्य आदि का प्रश्न है तो नरेंन्द्र मोदी से तो ऐसी उम्मीद करना ही व्यर्थ है, कॉग्रेंस का भी पिछलें साठ वर्षो का इस संबंध में कोई अच्छा रेकार्ड नहीं रहा है, नीतिश कुमार या अरविन्द केजरीवाल से कुछ उम्मीद है जिनका बनना अभी हवा में ही है।

देखिये ओर प्रतीक्षा करिये। देश की राजनैतिक क्षमता ऐसी बांझ हुई नही दिखती है कि वह संघ को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगी। देखिये और प्रतीक्षा करिये। मै तो राहुल गांधी को इस दौड से अलग देखकर संभावनाओ का आकलन कर रहा हूँ। जिसम नरेन्द्र मोदी अकेले ही मैदान मे खडे होकर गोल पर गोल मारते जा रहे है। समय आने दीजिये तब बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगा।

प्रश्न 4– विभिन्न अवसरो पर संघ परिवार के बारे मे आपके द्वारा दिया गया बयान कभी कभी विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप संघ की बुराइयों पर तीखा प्रहार करते है और दुसरी तरफ संघ के कारण भाजपा शासित प्रदेशो को कांग्रेस शासित प्रदेशो से बेहतर भी साबित करते है। आपका मनमोहन सिंह चिदम्बरम और राहुल गांधी प्रेम भी सर्वविदित है। आपका यह भी स्पष्ट मानना है कि भाजपा शाषित प्रदेशा मे स्वराज्य अथवा लोक स्वराज्य अथवा विकेन्द्रीयकरण के प्रति प्रतिबद्धता नही है। ऐसी स्थिति मे क्या यह संदेश नही जाता कि अथोक्रेट संघ के द्वारा संचालित पार्टी भाजपा शासित राज्य ही बेहतर प्रशासन दे सकते है और विकास भी कर सकते है फिर भाजपा पर संघ के हस्तक्षेप की आप खुलेआम आलोचना क्यो करते है?

उत्तर– प्रत्येक व्यक्ति मे कुछ गुण भी होते है और कुछ अवगुण भी। किसी एक विषय पर चर्चा करते समय जिस व्यक्ति की प्रशसा होती है उसी व्यक्ति की किसी अन्य विषय पर आलोचना भी संभव है। सर्वागीण प्रशंसा या सर्वागीण आलोचना बिरले लोगो की ही होती है। नरेन्द्र मोदी ने जिस कुशलता से गुजरात मे मुस्लिम साम्प्रदायिकता का फन कुचला अथवा सोहराबुद्दीन सरीखे अपराधियों से मुक्ति पाई उसके लिए वे हमेशा प्रशंसा के पात्र हैं किन्तु उन्ही नरेन्द्र मोदी की हरेन पंडया हत्याकॉड में ऑशिक भागीदारी भी पाई गई तो मोदी पूरो तरह घृणा के पात्र बन जावेंगें अथवा एक लडकी की अनधिकृत जासूसी के जो राज खुल रहे है या खुल सकते है वे तो नरेन्द्र मोदी सहित संध को भी डुबाने के लिये पर्याप्त हैं । किसी व्यक्ति की समीक्षा करतें समय घटना क्रम महत्वपूर्ण होता है। मैं मनमोहनसिंह, राहूल गॉधी का सर्वांगीण प्रशंसक हूँ। दूसरी ओर वही मै उसी कॉग्रेस पार्टी के अजोत जोगी का सर्वगींण आलोचक हूँ। छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, बिहार के मुख्यमंत्रियों का मैं प्रशंसक हूँ। इसी तरह दल के

रूप मे मैं अनेक मामलों में संघ का प्रशंसक हूँ और आलोचक भी इमानदारी त्याग के मामलें संघ का रेकार्ड सबसे अच्छा है। कार्य कशलता भी संघ मे पर्याप्त है। दसरी ओर हिटलरी सोच के मामलों में संघ हिन्दुओं का तालिबान ही है। संघ किसी भी तरह सर्वांगीण प्रशंसा का पात्र नही है। दूसरी ओर संघ किसी भी रूप मे सर्वांगीण आलोचना का भी पात्र नही है। संघ ने भाजपा पर नियंत्रण अवश्य कर लिया है **किन्तु यह** नियंत्रण अतिम नही हैं। आडवानी संघ से मात खा गये क्योंकि आडवानी जी मे पद लिप्सा भरी हुई थी। कोई निस्वार्थ व्यक्ति सामने होगा तब स्थिति बदल भी सकती है। अन्यथा मोदी जी बहुत शक्तिशाली हो गये तो वे सबसे पहले संघ परिवार से ही निपटेंगें। कोई तानाशाह किसी अन्य को अपने उपर नही देख सकता। मैं कोई भविष्य वक्ता नही हूँ किन्तु मुझे अब तक ऐसा ही दिख रहा है।

2/1 वैद्यराज आहूजा भानुप्रतापपुर जिला–कॉकेर छत्तीसगढ

विचारः ज्ञानतत्व 278 को पढा। दुबारा भी पढा। पिछले अनेक अंको की अपेक्षा इस अंक में मौलिकता अधिक है। वास्तव मे यदि ऐसा हो जाए तो नक्सलवाद का अपने आप समाधान हो जाएगा। इतने अच्छे और गंभीर विचार आप नेताओं विशेषकर वामपंथी नेताओं को अवश्य भेजिए, जिससे उनकी सोच मे कुछ बदलाव आ सके।

प्रश्न 2/2 श्री महेन्द्र नेह, कोटा राजस्थान

विचार — ज्ञान तत्व निरंतर प्राप्त हो रहा है। आप देश की समस्याओ के बारे मे खूब चिंतन करते है, और उन्हे हल करने की युक्ति भी ढूढते है। समाधान भी प्रस्तुत करते है । यह अपने आप मे लीक से हटकर प्रयत्न ह। आप अपनी बात सार्वजनिक भी करते है। मैने अभी अभी आपके 278वे अंक को पढा है। आपने श्रम समस्या और अर्थ तंत्र के बारे मे काफी हद तक मौलिक व व्यावहारिक सुझाव सामने रखे है। खास तौर पर श्रम उर्जा एवं कृत्रिम उर्जा के बारे मे। सवाल यह है कि अपनी अवधारणा को आप किस तरह सम्पूर्ण रूप स लागू करवा पायेग ? क्या आप तंत्र को बदल पायेंग या फिर समाज को अपनी सोच के आर्थिक सूत्र मे ढाल पायेंगे? आप किस तरह कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढा पायेगे? जिससे श्रम उर्जा का सम्मान हो सके। कब मरेगी सास और कब आयेगे आसू?

और कुछ हो या न हो आपके इस सुझाव से देश के पूंजीपति अवश्य सहमत हा जायेग कि न्यूनतम वेतन को बढाने के बजाय मशीनो को अधिक महगा किया जाये। पूंजीपतियो का एक मात्र उददेश्य यह है कि उसे बाजार मे सस्ते से सस्ता श्रम उपलब्ध हो तथा उसकी मिलो मे उत्पादित मशीने अधिक से अधिक महगें भावो मे बिके। अपनी व्याख्या मे आपको इस बात की बडी फिक्र रहती है कि किसी भी तर्क द्वारा मार्क्स को असफल सिद्ध किया जाये और गांधी को विकल्प के रूप मे पेश किया जाये । आपने श्रमउर्जा और कृत्रिम उर्जा के तुलनात्मक अध्ययन मे भी मार्क्स की श्रम नीति को असफल सिद्ध कर दिया। गांधी जो की श्रम नीति को वर्धा मे पावर लूथ लगा कर पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों ने असफल कर दिया।

मै समझना चाहता हूँ कि क्या आप सभी बुद्धिजीवियो को एक जैसा ही मानते है ? जिनका काम स्वयं के लिये सुविधॉए जुटाना है, और वे पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रमिकों के शोषण मे शामिल ह। लगता है श्रमजीवी बुद्धिजीवियो को आप देखना नही चाहते और केवल पूंजीपतियों के चाकर बुद्धिजीवियों को ही रेखांकित करना चाहते है।

मुझे लगता है कि आप समझते है कि वर्तमान अर्थ तंत्र जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी अर्थतंत्र है इसका समाधान कुछ सुधार लागु करके या नियमो मे परिवर्तन करके संभव है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अपने नियम और प्रवृत्तियां होती है। वैदिक समाज मे सामूहिक श्रम से उत्पन्न वस्तुओ /उत्पादन को आपस मे बराबर बाटने का नियम था। दास प्रथा मे प्रभुवर्ग ने समस्त उत्पादन व श्रम शक्ति का एक मात्र ध्रुव एक मात्र स्वामी स्वयं को बना लिया और दासो को पूरी तरह अधिकार विहीन कर दिया। सामंती समाज मे श्रमिक किसान को एक हिस्सा देना स्वीकार किया गया लेकिन टैक्सो व लगानो के जरिये उकी चमडी उतार लेने मे कोई कमी नही रखी गई। हमारे देश समाज मे तो श्रम का कृत्रिम विभाजन करके वर्ण व्यवस्था को नैतिक व धार्मिक नियम के रूप मे ही लागू कर दिया गया। पूंजी वादी व्यवस्था ने अपने प्रारंभिक दौर मे श्रम को आजाद करने का काम किया ताकि अपने कारखाने की श्रम पूर्ति हा सके । लेकिन वर्तमान दौर मे उसने मरणशील सामन्तवाद से समझौता करके जाति धर्म सम्प्रदायवाद श्रेत्रियतावाद को बढावा देकर श्रमजीवी समुदाय के संघर्ष को ही कुन्द कर दिया। न श्रमिक अपने अधिकारो के लिये लाभवन्द होगे और न ही व्यवस्था परिवर्तन की लडाई तेज हो सकेंगी।

आप पूंजीवादी अर्थतंत्र समाजवादी अर्थ तंत्र को एक ही पलडे मे तौलते है जबकि दोनो हक दूसर से पूरी तरह भिन्न है पूंजीवादी तंत्र शोषण का तंत्र है। जबकि समाजवाद का उददेश्य शोषण विहीन समाज की ओर बढता हैं। जब शोषण विहीन समाज बनेगा तो उसमे पैसे की जगह मनुष्य का सम्मान सर्वोपरि होगा। श्रम के लिये सर्वाधिक स्वस्थ एंव अकृत्रिम वातावरण सृजित किया जायेगा। इसका लाभ केवल श्रमिको के नही पूरी समाज व्यवस्था को मिलगे। समाज से सभी ऋणात्मक स्थितियों विस्थापित करके धनात्मक व सृजनात्मक स्थितियॉ निर्मित की जायेगी। जिस तरह राजे महाराजों का वर्चस्व क्षीण हुआ। समाजवादी समाज मे एक स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा लूटखोर ताकतो व तंत्र को निर्मूल व निस्तेज कर दिया जायेगा। यह काम केवल बल पूर्वक नही अपितु सांस्कृतिक व मानवोचित ढंग से भी किया जायेगा । कभी इस दिशा मे भी सोच, विचार व अमल की ओर बढे।

उत्तरः — समाज में न सभी बुद्धिजीवी जानबूझकर श्रम शोषण की योजनाएँ बनातें हैं न सभी पूंजीपति। स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनेताओं ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सस्ती उर्जा की शुरूवात की। हो सकता हैं कि उनसे भूल ही हुई हो किन्तु इस योजना में श्रम खरीदने वालों को मजा आने लगा। वामपंथियों ने श्रम बेचने वालों का प्रतिनिधि बनकर श्रम बेचनेवालों को श्रम खरीदने वालों के विरूद्ध भडकाना शुरू किया जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। वर्ग संघष के लिए आवश्यक है कि कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति प्राकृतिक रूप से कभी न सुधरे तथा उसे संघर्ष के माध्यम से थोडा थोडा लाभ मिलता रहे। आवश्यक था कि इस उद्देश्य के लिए कृत्रिम उर्जा को मंहगा न होने दिया जाए।श्रम खरीदने वाले बुद्धजीवी पूँजीपति तथा सरकार कृत्रिम उर्जा के सस्ता रहने से प्रसन्न थी तो दूसरी ओर श्रम बेचने वालों को वामपंथियों ने समझा दिया था कि कृत्रिम उर्जा को सस्ता होना चाहिए। विश्व परिदृश्य बदला तो भारत के वामपंथियों को रूस चीन से मिलने वाली आर्थिक सहायता कम हा गई। इन्हें राजनैतिक आर्थिक सहायता के लिए खाडी के देंशों की ओर देखना आवश्यक हो गया।बदलें मे इन्हें खाडी देशों से भारत आने वाले डीजल, पटो्ल की खपत न घटने की वकालत करनी पडी। वामपंथियों ने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। इन्होनें भारत में हर बिजली परियोजना मे रोडे अटकाए इन्होनें डीजल, पेट्ोल की मूल्य वृद्धि का भरपूर विरोध किया। वामपथियों की इस विरोध पहल का भाजपा सहित सभी दक्षिण पंथी ताकतों नें समर्थन किया, क्योंकि दक्षिणपंथी तो स्वाभविक रूप से श्रम खरीदने वालों के पक्षधर माने जातें हैं। फिर भी यदि यह बात बुद्धिजीवियों को समझाई जावे तो उनमें से अनेक बुद्धिजीवी समझेंगें। यदि दस प्रतिशत बुद्धिजीवी भी मुखर हो गये तो यह काम कठिन नही रहेगा। वर्तमान समय में तंत्र तो इसलिए इस बात से डर रहा है कि कहीं लोक नाराज न हो जावे। किन्तु लोक ऐसी मॉग उठाना ' शुरू कर देगा तो यह कार्य आसान हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें।

मैने मशीनों को महॅगा करने की बात नही की है। मैं तो सब प्रकार की मशीनों पर से टैक्स हटाकर उहें सस्ता करना चाहता हूँ। यदि मशीनें मॅहगी और उसमें खपत होने वाले डीजल, पेट्ोल बिजली, कोयला सस्तें होंगें तो इसका विपरीत प्रभाव होगा। मेरा मत है कि मशीनें चाहे सस्ती हों या मॅहगी उसका कोई प्रभाव नही होगा किन्तु डीजल पेट्ोल मॅहगा होगा तो उसका निश्चित प्रभाव होगा ।

आपने मुझ पर येन केन प्रकारेण मार्कस को असफल सिद्ध करके गॉधी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। यही आरोप मैं आप पर पलट दूँ कि आप येन केन प्रकारेण मार्कस को सफल आर गॉधी का विरोध करने का बीडा उठायें हैं तो न आपका आरोप स्थापित हो पाएगा न मेरा । सच्चाई यह है कि आरोप को प्रमाणित करने के लिए तर्क चाहिए। यह बात सच है कि मैंने मार्कस को असफल और गॉधी को सफल माना है और इस पर एक किताब आपको भेजी है। आप उस किताब के तर्कों की समीक्षा करके उसकी कुछ बातों को गलत प्रमाणित करनें के तर्क दे ंतब तो आपका मार्कस पम विचार मंथन मे कुछ टिक सकता है_अन्यथा आपका कथन आपकी खींझ से आगे नही बढ पाएगा। आशा है कि आप ज्ञानतत्व का वह अंक दुबारा पढकर उसकी मार्कस प्रेमी समीक्षा भेजने का कष्ट करेंगें।

यदि साम्यवाद ने दास प्रथा से समाज को मुक्त करने का एक पवित्र कार्य किया है तो अब साम्यवाद इसके बदले मे कब तक समाज को दास बनाकर रखना चाहता है? आप श्रम जीवी वर्ग को गिरी पिछडी हालत में रखकर उसे वर्ग संघर्ष के लिए तैयार करना चाहतें हैं जबकि मैं चाहता हूँ कि श्रमजीवी बुद्धिजीवी पूँजीपति के बीच की दूरी घटें और वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति अपने आप बेमौत मर जावे। मैं समझता हूँ कि वर्ग संघर्ष कभी एक समाधान रहा होगा किन्तु आज तो अनिवार्य नही है।

मार्कसवादी असफल नही है। उन्होनें तो भरपूर त्याग भी किया है और संघर्ष भी। मार्कसवाद एक असफल और घातक विचार है। वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाना कोई अच्छी बात नही। वर्ग समन्वय का मार्ग ही उचित_मार्ग है।

आशा है कि आप साम्यवाद की घिसी पिटी लाइन छोडकर तर्क संगत समीक्षा भेंजेंगें।

3 छवील सिंह सिसोदिया, पिलखुआ हापुण उत्तर प्रदेश

विचार — मैने राष्ट्रपति जी का पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केन्द्र व राज्य सरकारों को जाति धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर झगडा करने से रोका जाय । वोटो के ध्रुवीकरण मे दो सम्प्रदायों का खूनी संघर्ष व पुलिस व जनता का खूनी संघर्ष उत्तर प्रदेश की तरह से अधिकाशं राज्यो मे होने लगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले मे दूसरे सम्प्रदाय की लडकी की छेडछाड मे दो सम्प्रदायों के हुए खूनी संघर्ष की आग पुलिस की उपस्थिति मे सात जिलो तक फैली । सैकडो लोगो की जाने चली गई। किसानो के करोडो रूपये के क्षतिग्रस्त ट्रेक्टर घायल व मृतको सहित नहर मे डाल दिये गयें। मेरठ के खेडा गांव की महिलाओ को पुलिस से पिटवाया गया। बताया जा रहा है कि लडकी के मृतक भाई सचिन व गौरव के हत्यारो को अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खा ने आज तक गिरफतार नही होने दिया । निर्दोष सैकडो लोग सरकार की साजिश से मारे गये है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने अपनी रिर्पोट मे केन्द्र को लिख कर भेजा है कि झगडे कराने के लिये राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नही करके वोटो के ध्रुवीकरण को बनाने का कार्य किया है।

1 अन्ना आंदोलन मे जन लोक पाल बिल पास न करके सभी राजनैतिक दलो की एकता ने भ्रष्टाचार बनाये रखने की नीयत पहले ही साबित कर दिया है।

2 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट कर अपराधियों को संसद मे भेजने के स्वीकृत अध्यादेश को पेश करके अपराधियों का वर्चस्व बनाये रखने की नीयत से अवगत कराना साबित किया है।

3 राजनैतिक दलो की एकता मे जनप्रतिनिधियों को आर टी आई से बाहर रखने की नीयत से तानाशाही वृत्ति का भी परिचय दिया।

अंग्रेज लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से/ भारतीयों का मर्यादित रीति रिवाज व्यवहार रहन सहन व युवक युवतियों की गौरवान्वित पौशाको को साजिश से बदलवाया जा सकता है। 1935 मे बने कानून व 1946–47 की तानाशाही मे बने संविधान की भ्रष्ट हुई व्यवस्था से भारतीयों को जीने के लिये बाध्य किया जाना अलोकतांन्त्रिक है।

लोकतंत्र युवावस्था की ओर बढ रहा है। उपरोक्त अवधि मे बना तानाशाही संविधान व कानून निष्प्रभावी व बूढा हो रहा है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिये संविधान मे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिय राष्ट्रहित मे संशोधन करना आवश्यक हो गया है। लोकतंत्र मे आम आदमी की तरह सिपाही से लेकर मंत्री तक पर अपराध बलात्कार व भ्रष्टाचार मे पुलिस व सी बी आई को सीधे कार्यवाही के लिये अधिकृत किया जाय।

यह देश किसी जाति धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है। एक अरब बीस करोड लोगो की आबादी का समूह भारतीय संघ है। प्रत्येक गरीब दुर्बल व असहाय विकास की योजनाओ की सहायता का पात्र है व प्रत्येक जाति सम्प्रदाय का व्यक्ति व समूह को सुरक्षा व न्याय देना शासन का दायित्व ह। देश के किसान मजदूर के खून पसीने की कमाई के वसूले टैक्स से व अमीरो से वसूले टैक्स के धन से देश का विकास हो रहा है तथा भ्रष्टाचार व घोटाला करके सत्ताधारी जनता के इस धन को लूट रहे है।

भ्रष्टाचार लूट व अपराध पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था परिवर्तन करना ही एक मात्र विकल्प है। सत्ता परिवर्तन करते रहना केवल भ्रष्टाचार को बनाये रखना है।

समाज लोकतंत्र के नाम पर केन्द्र व राज्य सरकार की संदिग्ध कार्यवाही को नजदीक से समझ व देख रहा है कि शासक की विश्वसनीयता व निष्पक्षता मे कभी किसी अकेले सिपाही व किसी कर्मचारी पर समाज ने उंगली तक इसलिये नही उठाई कि शासकीय कार्यवाही निष्पक्ष थी। आज पुलिस के समूह के साथ एस पी व डी एम प्रशासन झगडा व नियंत्रण मे स्वयं घायल होने व पिटने लगा मंत्रियो पर जूते चप्पल तक फैके जाने लगे व्यवस्था की खिल्ली उडाई जा रही हैं शासको की अयोग्यता देश का वातावरण विगाडने के लिये जिम्मेदार है।

नैतिकता महसूर करे तो माननीय शासको के लिये खेद का विषय है चिन्तन का विषय है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि केन्द्र व राज्य सरकारो को जाति धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही से रोका जाय ताकि देश की अखंडता बनी रहे। लोकतंत्र अपने पैर से चले । मुजफ्फर के साम्प्रदायिक झगडे मे मारे गये लोगो की जिम्मेदारी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये एंव केन्द्र को भी निर्देशित किया जाय कि अपने दायित्वो के प्रति सचेत रहे। आपकी अति कृपा होगी कि की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

छ उत्तरार्ध

नोट–अगर आप कुछ ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका की राशि जमा करना चाहते है तो आप बजरंग लाल अग्रवाल , एस बी आई 11374646729 रामानुजगंज जिला–बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ मे आप पैसा जमा करा सकते है। आप मनियार्डर भेज सकते हैं अथवा आप बजरंग अग्रवाल अथवा बजंरंग मुनि , बनारस चाक, अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगड के लिए चेक के द्वारा भी पैसा जमा करा सकते है।